

4.75 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करेगा बजट

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर सीएम के सामने दिया गया प्रेजेंटेशन

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 10 फरवरी. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार का बजट 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपए के आंकड़ को पार कर सकता है. बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 15 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.

वहीं, राजकोषीय घाटे को सरकार 4.50 फीसदी के दायरे में लाने की कोशिश करेगी. राज्य सरकार का बजट 18 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा. इससे

एनसीएल निगाही परियोजना में मजदूरी घोटाला

पीड़ित मजदूर ने कलेक्टर से लगाई गुहार

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 10 फरवरी। एनसीएल निगाही परियोजना के अंतर्गत कार्यरत निजी कंपनी क्लाउट टेक प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा पर मजदूरों के शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

ग्राम जैतपुर चौकी जयन्त निवासी गरीब मजदूर विनोद कुमार साकेत ने कलेक्टर को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा उसे पिछले 15-16 माह से पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और आवाज उठाने पर अकारण ट्रांसफर कर काम से बाहर कर दिया गया। पीड़ित मजदूर के अनुसार उसकी निर्धारित मासिक मजदूरी 19,130 रुपये है, लेकिन ठेकेदार द्वारा उसे केवल 10,560 रुपये प्रतिमाह दिए गए। शेष राशि हड़प ली गई। जब मजदूर ने अपनी पूरी मजदूरी की मांग की तो ठेकेदार व कंपनी के जिम्मेदारों ने गाली-गलौज की और विवाद का वीडियो भी बनाए, जो अब सबूत के रूप में मौजूद है। मजदूरी मांगना ही मजदूर के लिए अपराध बन गया और बदले में उसे जबरन अन्य स्थान पर



एक दिन पहले मप्र का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा. नए वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर मंगलवार को मंत्रालय में पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया, बाद में पूरी कैबिनेट के सामने अপর मुख्

सचिव वित्त मनीष रस्तोगी ने प्रेजेंटेशन दिया. ये प्रजेंटेशन लगभग एक घंटे तक चला. इस दौरान सभी विभागों से जुड़ी प्रावधानों के बारे में बताया गया. मौजूदा वित्तीय वर्ष का बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का

है. इस हिसाब से देखें तो नये बजट में कम से कम 54 हजार करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी होगी. बजट में सबसे अधिक राशि का प्रावधान यदि किसी एक योजना के लिए होगा तो वह मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना होगा, जिसके लिए इस बार राज्य सरकार 21 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि

का प्रावधान करेगी. इसी तरह एक बार फिर जल जीवन मिशन के लिए भारी-भरकम राशि का ईतजाम करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार के कंधे पर होगी, ये इसलिए कि अब तक केंद्र सरकार ने मिशन के तहत हुए कामों का 8 हजार करोड़ रुपए का बकाया केंद्र सरकार से नहीं मिला है.

निकाय और पंचायत चुनाव में आईटी का बेहतर उपयोग करेगा आयोग

► राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की समीक्षा बैठक

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 10 फरवरी. मप्र राज्य निर्वाचन आयोग आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत आम निर्वाचन-2027 में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करेगा. इससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में मदद मिलेगी.

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने मंगलवार को इस कार्य की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां समय-सीमा में पूरी करें. बैठक में केन्द्र

सरकार की संस्था एनआईसीएसआई के प्रतिनिधि ने स्थानीय निर्वाचन में मतदाता, मतदान, ट्रेकिंग टूल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक एवं एआई. आधारित मतदाता सूची एवं मतदाता सत्यापन सहित अन्य सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया. उन्होंने आयोग के अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचन प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग से कुछ अलग है. इसलिए इसे ध्यान में रखकर ऐप बनायें.

बरका पटवारी के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा पैसे बिना नहीं होता कोई काम, तीन साल से जमे पटवारी पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 10 फरवरी। देवसर तहसील के ग्राम बरका हल्का नंबर 29 में तैनात पटवारी रामखेलावन सिंह के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा आज दिन मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में फूट पड़ा।

दर्जनों किसान शिकायत लेकर पहुंचे और आरोप लगाया कि पटवारी बिना पैसे लिए कोई भी सरकारी काम नहीं करता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जमीन बंटवारा, नक्शा तरमीनी और खसरा सुधार जैसे जरूरी कार्य महीनों तक लटकाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तीन वर्षों से एक ही स्थान पर जमे



पटवारी ने भ्रष्टाचार को आदत बना लिया है।

कई किसानों ने बताया कि रिश्तत देने के बाद भी फाइलें धूल खा रही हैं। इससे किसानों को मानसिक तनाव के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस

कार्रवाई नहीं हुई, जिससे गांव में आक्रोश और अविश्वास गहराता जा रहा है। कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में विजय जायसवाल, रामजी गुप्ता, राजेश जायसवाल, प्रेमसागर जायसवाल सहित अनेक ग्रामीणों ने पटवारी को तत्काल हटाने और निष्पक्ष जांच की मांग की।

दुष्कर्मों को 20 वर्ष का कठोर कारावास

छिंदवाड़ा. मासूम बालिका के साथ दुष्कृत्य करने के मामले में आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनते हुए दुष्कर्मी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. घटना 25 जून 2025 के दोपहर करीब 12 बजे की बात है मासूम बालिका के पिता मजदूरी करने गये थे और मां घर में नहीं थी फिर जब मां वापस घर आयी तब मां ने देखा कि उसकी 4 साल की बेटी घर पर नहीं है तब मोहल्ले वालों ने बताया कि आरोपी दुरंगेश लड़की को डेम तरफ लेकर गया है तब बालिका को मां तुरंत पंहे पहुँची वहा देखा कि लोगों की भीड़ लगी थी और बालिका बहुत रो रही थी. उसके साथ दुष्कर्म हुआ था.

नाम परिवर्तन सूचना

मै राजीव सिंह भदौरिया पिता महेन्द्र सिंह भदौरिया अम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम बंशीपुर थाना मेहर तह. मेहर जिला मेहर म.प्र. का निवासी होकर बहलफ सूचित कर रहा हुं. कि मेरा आधार कार्ड नं.641805673359 है, मै अपने पासपोर्ट को रिनू करना चाहता हुं जिसमें मेरा नाम राजीव सिंह लेख है जबकि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व सप्प्रा आईडी में मेरा नाम राजीव सिंह भदौरिया है, उक्त दोनों नाम राजीव सिंह भदौरिया और राजीव सिंह दोनों नाम मेरे ही है यानी एक ही व्यक्ति के है अलग-अलग नहीं है .

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना एवं प्रदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग सतना			सतना, दिनांक : 05/02/2026		
क्रमांक- 192 / भू अर्जन / 2026			अधिसूचना		
म0प्र0पा0ज0क0लि0 सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम मझियार कोटार तहसील रामपुरबाधेलन जिला सतना म0प्र0 की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां दूध क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक - 4 अनुसार वापस की जाना है ।			अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन :- (म.प्र. शासन / निजी खाता)			(क) जिला – सतना		
			(ख) तहसील – रामपुर बाधेलान		
			(ग) नगर / ग्राम – मझियार कोटार		
			(घ) क्षेत्रफल / रकबा – 38.187 हे०		
सरल क्रमांक	वापसी योग्य खसरा क्रमांक	वापसी योग्य रकबा (हेब्टेयर)	सरल क्रमांक	वापसी योग्य खसरा क्रमांक	वापसी योग्य रकबा (हेब्टेयर)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	38	0.295	101	78	0.198
2	43	0.131	102	79	0.717
3	48	0.198	103	246	0.117
4	50	0.227	104	247	0.049
5	51	0.223	105	292	0.200
6	52/1	0.206	106	67	0.178
7	53/1	0.190	107	68	0.053
8	61	0.243	108	69/1	0.125
9	191	0.178	109	285	0.214
10	87	0.105	110	69/2	0.121
11	3	0.114	111	93	0.256
12	100/2	0.142	112	73	0.202
13	178	0.202	113	76/1	0.291
14	186	0.085	114	82	0.239
15	204	0.109	115	83	0.150
16	190	0.073	116	85	0.250
17	193	0.202	117	81	0.470
18	201	0.142	118	91	0.178
19	202	0.024	119	92/1	0.239
20	203	0.073	120	210/1	0.162
21	205	0.166	121	235/1	0.174
22	207/2	0.036	122	242/1	0.200
23	243	0.441	123	253/1	0.145
24	261	0.414	124	254/1	0.247
25	206	0.186	125	255/1	0.324
26	209	0.003	126	218	0.040
27	62	0.166	127	100	1.076
28	72	0.279	128	101	0.450
29	222	0.028	129	102	0.049
30	7	0.287	130	111/2	0.170
31	113	1.250	131	112/2	0.045
32	174	0.745	132	111/3	0.040
33	175	0.578	133	112/1	0.134
34	177	0.299	134	234	0.150
35	264	0.194	135	262	0.100
36	265	0.049	136	263	0.057
37	266	0.040	137	223/1	0.016
38	280	0.140	138	224/1	0.032
39	281	0.040	139	225	0.049
40	41	0.040	140	227	0.053
41	42	0.813	141	223/2	0.020
42	15	0.400	142	224/2	0.004
43	66	0.170	143	179	0.271
44	257	0.030	144	207/3	0.044
45	16	0.138	145	192/1क	0.385
46	17	0.648	146	173	0.356
47	56	0.109	147	250	0.231
48	57	0.773	148	288	0.384
49	58	0.356	149	180	0.271
50	75	0.239	150	181	0.166
51	111	0.121	151	182/2	0.170
52	230	0.049	152	184	0.376
53	231	0.065	153	198/1	0.146
54	251	0.105	154	199/2	0.405
55	252	0.125	155	183/1	0.700
56	258	0.162	156	192/2/1	0.012
57	259	0.121	157	192/2/2	0.012
58	267	0.223	158	194	0.061
59	270	0.206	159	195	0.113
60	103	1.319	160	207/1क	0.024
61	268	0.316	161	207/1ख	0.020
62	21	0.498	162	207/1ग	0.020
63	53/2	0.458	163	211	0.040
64	189	0.198	164	215	0.053
65	196	0.097	165	228/2	0.049
66	216	0.105	166	228/1	0.057
67	217	0.061	167	238	0.109
68	271	0.526	168	239/1क	0.073
69	272	0.125	169	240/1	0.036
70	273	0.069	170	269	0.045
71	274	0.040	171	286	0.275
72	275	0.134	172	290	0.182
73	276	0.247	173	229	0.125
74	279	0.267	174	70	0.109
75	74	0.344	175	71	0.279
76	25	0.547	176	86	0.097
77	121	0.300	177	88	0.045
78	244	0.040	178	89	0.024
79	245	0.320	179	90/1	0.021
80	239/1 ख	0.073	180	90/2	0.020
81	240/2	0.040	181	90/3	0.020
82	120	0.200	182	197	0.065
83	176	0.494	183	198/2	0.008
84	236	0.206	184	204	0.101
85	199/1	0.146	185	208	0.174
86	241/1	0.316	186	220	0.028
87	260	0.166	योग	186 क्तिता	38.187
88	76/2	0.085	म0प्र0पा0ज0क0लि0 सिरमौर निजी खाता भूमि योग रकबा – 38. 187 हे०		
89	39	0.259	(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भू- अर्जन संभाग म0प्र0पा0ज0क0लि0 सिरमौर (म0प्र0) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि दूध क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों / उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु ।		
90	40	0.494	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।		
91	44	0.113	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार		
92	47	0.206	(डॉ. सतीश कुमार एस.)		
93	49	0.275	कलेक्टर		
94	60	0.263	जिला सतना (म0प्र0)		
95	45	0.093	एवं पदेन उपसचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग		
96	54	0.040	G-25684/25		
97	55	0.198			
98	64	0.174			
99	65	0.231			
100	77	0.522			

भ्रामक नंबर प्लेटों पर लगे रोक

नवभारत न्यूज
चाकघाट 10 फरवरी, परिवहन विभाग की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण चार पहिया अथवा बाइक में कुछ लोग इस प्रकार का भ्रमित करने वाला नंबर प्लेट लगाकर चलते हैं मानो की उन्होंने अत्यंत ही कलात्मक से डिजाइन से नंबर लिखा कर अपना रसुक प्रदर्शित कर रहे हो, किंतु इस तरह के नंबर प्लेट वाले वहां से कुछ अनहोनी या प्रतिबंधित कार्य हो जाए जो शासन-प्रशासन इसकी खोजबीन किस आधार पर करेगा । इसके अलावा शासकीय

वाहनों में बिना अधिकारी के उपस्थिति के हूटर को बजाना, एंबुलेंस में बिना मरीज के तीव्र गति से सायरन बजाते हुए मार्केट के बीच से वाहन को ले जाना इत्यादि समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी महोदय से मांग है, कि इस प्रकार के भ्रामक नंबर प्लेटों पर तत्काल कार्रवाई

कर उन्हें सामान्य तरीके से समझ में आने वाले डिजिट (अक्षरों) से नंबर लिखाकर वाहनों पर लगाने की सख्त हिदायत देना चाहिए, जिससे सामान्य जनमानस को उनके वाहन का नंबर स्पष्ट रूप से पढ़ने में आ सके ।

पेज एक का शेष एमपी में अब परिवार पेंशन का बढ़ा दायरा

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और ई-सेवा पुस्तिका संबंधी प्रावधान किया गया है. केन्द्र तथा मप्र शासन की पूर्व सेवाओं को जोड़ा जायेगा. निलम्बन अवधि में अभिदाता तथा नियोका के अंशदान का प्रावधान किया है.

इसके साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत एवं स्पष्ट प्रक्रिया, अंशदान की दर, गणना एवं विलंब की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारण के साथ सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र एवं मृत्यु की दशा में निकास प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले

शासकीय सेवकों के लिए उपदान की पात्रता निर्धारण एवं भुगतान की सुस्पष्ट प्रक्रिया होगी. विभागीय जांच (सेवा निवृत्ति उपरांत) आदेश के संदर्भ में उपदान से वसूली संभव होगी.

विभागीय जांच की अवधि में नियोका के अंशदान का भुगतान रोक़ा जाने का प्रावधान किया गया है. इसी तरह सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व अभिदाता अंशदान रोक़ा जाना और सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच संस्थित किये जाने का प्रावधान के साथ नियमों में बदलाव का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा.

ये निर्णय भी लिए

- वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जनजातीय कार्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की निरंतरता के लिए 7, 133 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति.

-उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के आई टी संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को तकनीकी संवर्ग की प्रचलित और भावी भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सिर्फ एक बार के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की स्वीकृति प्रदान की गई. वर्तमान में अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है.



कार्यालय प्राचार्य, रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
(शासन द्वारा स्थापनित घोषित)
दूरभाष : 07662-233478 फ़ैक्स : 07662-233478
वेबसाइट : http://www.recrewa.ac.in, ईमेल : principal@recrewa@gmail.com
क्रमांक / आर.ई.सी.आर / मैक. / निविदा / केब उपकरण / 2026 / 321 1 वी. दिनांक 05/02/26

ई – निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

प्राचार्य रीवा इंजीनियरिंग कोलेज रीवा म. प्र. द्वारा मैकेनिकल इंजी. विभाग में उपकरणों (Exhaust gas analyser and smoke meter) का क्रय करने बाबत पात्र फर्मों से एन पी ई टेंडर पॉर्टल (ऑन लाइन पद्धति) के माध्यम से ई निविदाये (द्वितीय आमंत्रण) आमंत्रित की जाती है । निविदा प्राप्त की विस्तृत जानकारी मप्र शासन के ई टेंडरिंग पोर्टल (www.mptenders.gov.in